

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1460
जिसका उत्तर 4दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13 अग्राहायण, 1946 (शक)

चिप्स के लिए नवोन्मेषों को प्रोत्साहन

1460.श्री एस. जगतरेखन:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि देश को ऐसे नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो तीव्र, सस्ते और अधिक शक्तिशाली चिप्स की निरंतर बढ़ती मांगों को पूरा करते हों जिसमें स्टार्टअप्स और निजी अनुसंधान संस्थानों को और अधिक निधि प्रदान करना शामिल है, जिस प्रकार अमरीका उन परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है जिनसे समाज के लिए कई सारे मूल्य सृजित किए जा सकते हैं; और
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं
(ख):सरकार देशकेभीतरअनुसंधानऔरनवाचारकोबढ़ावादेनेपरजोरदेतेहुएसमग्रसेमीकंडक्टरडिजाइनऔरविनिर्माणइकोसिस्टम केनिर्माणकेअपनेउद्देश्यपरकेंद्रितहै। इसेपूराकरनेकेलिए, कईपहलकीगईहैं, जिनमेंआरएंडडी (अनुसंधानऔरविकास) औरविनिर्माणबुनियादीढांचेकीस्थापना, क्षमतानिर्माणपहलेंऔरकार्यबलअंतरालकोदूरकरनेकेलिएकौशलविकासकार्यक्रमशामिलहैं। सरकारप्रौद्योगिकीकोआगेबढ़ानेकेलिएआरएंडडी पहलोंकाभीसमर्थनकरतीहैऔरस्टार्टअपऔरनिजीअनुसंधानसंस्थानोंकोप्रोत्साहन देती है, जिससेउन्हेंसामाजिकआवश्यकताओंकोपूराकरनेकेलिएसेमीकंडक्टरचिपडिजाइनजैसेक्षेत्रोंमेंए समाधानबनानेकेलिएप्रोत्साहितकियाजाताहै। भारतसरकारकीइनपहलोंमेंसेकुछमेंनिम्नलिखितशामिलहैं, लेकिनये इन्हींतकसीमितनहींहैं:

- (i) चिपडिजाइनमेंउद्योग के लिए तैयारजनशक्तिबनाना: चिप्सटूस्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रमदेशभरमेंफैले 113 शैक्षणिकसंगठनों (जिसमें 100 शैक्षणिकसंस्थान/आरएंडडीसंगठनऔर 13 स्टार्ट-अप/एमएसएमईशामिलहैं) मेंवर्ष 2022 मेंइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वाराशुरूकियागयाएकव्यापकक्षमतानिर्माणकार्यक्रमहैजिसकापरिव्यय 5 वर्षोंकेलिए 250 करोड़रुपयेहोगा। सी2एस कार्यक्रमकाउद्देश्यसेमीकंडक्टरचिपडिजाइन, वीएलएसआई (बहुतबड़ेपैमानेपरएकीकरण) औरएम्बेडेडसिस्टमडिजाइनक्षेत्रोंमेंविशेषज्ञताप्राप्तबी.टेक, एम.टेकऔरपीएचडीस्तरपरउद्योग-तत्पर 85,000 मानवशक्तितैयारकरनाऔरदेशमेंजीवंतफैबलेसचिपडिजाइनइकोसिस्टम बनानाहै।

सी2एस कार्यक्रमछात्रोंकोव्यापक रूप से चिपडिजाइन, निर्माणऔरपरीक्षणमेंपूर्णव्यावहारिकअनुभवप्रदान करता है। यहउद्योगभागीदारोंकेसहयोगसेआयोजितनियमितप्रशिक्षणसत्रोंकेमाध्यमसेप्राप्तकियाजाताहैऔरछात्रोंकोचिपडिजाइन, निर्माणऔरपरीक्षणसंसाधनोंतकपहुंचऔरमार्गदर्शनप्रदानकरकेप्राप्तकियाजाताहै, जिसमेंअत्याधुनिकईडीए (इलेक्ट्रॉनिकडिजाइनऑटोमेशन) उपकरण,

चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर फाउंड्री तक पहुंच आदि शामिल हैं। इन अवसरों में एसआईसीएस (एप्लिकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट), सिस्टम/एसओसीएस (सिस्टम-ऑन-चिप्स), और आईपी (बौद्धिक संपदा) कोर डिजाइन के कार्यशील प्रोटोटाइप के विकास के लिए सी२एस कार्यक्रम के तहत आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) परियोजनाओं को लागू करना शामिल है।

- (ii) **सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं वाचारइकोसिस्टम को सहायता :** एमईआईटीवाई शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और स्टार्टअप कंपनियों में रणनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। इनमें से कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं हैं- 32-बिट/64-बिट मल्टी-कोर माइक्रोप्रोसेसरों की एक श्रृंखला का डिजाइन, विकास और निर्माण, अन्य एप्लीकेशनों के साथ-साथ स्वदेशी प्रोसेसर, फोटोनिक्स/क्वॉंटम चिप्स का उपयोग कर नाविक (नेविगेशन विडिंडियन कांस्टेलेशन) रिसीवर और डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स (डीपीएचए) के लिए चिपसेट। इन पहलों के परिणामस्वरूप चिप डिजाइन क्षेत्र में स्टार्ट-अप भी बने हैं।

(iii) **सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना:**

भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्सेल्ड कोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 'सेमीकंडक्टर और डिस्सेल्ड कोसिस्टम के लिए संशोधित कार्यक्रम' को मंजूरी दी है। इसके एक हिस्से के रूप में डिजाइन लिंकडिसेंटिव (डीएलआई) योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका परिव्यय 1000

करोड़ रुपये है ताकि घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन उद्योग में कमियों को दूर किया जा सके और साथ ही मूल्य-श्रृंखला में आगे बढ़ा जा सके और देश में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।

डीएलआई योजना सेमीकंडक्टर चिप्स के विकास और परिनियोजन के विभिन्न चरणों में घरेलू कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना सहायता देती है।

डीएलआई योजना के तहत 42 डिजाइन कंपनियों (स्टार्ट-अप और एमएसएमई सहित) को डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें से 15 कंपनियों को ऑटोमोटिव, मोबिलिटी, कंप्यूटिंग, संचार आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए सेमीकंडक्टर चिप/एसओसी विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए भी मंजूरी दी गई है।
